जी.सी.मितल, जे.शर्मा एंड कंपनी से पहले,-

याचिकाकर्ता।

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश और अन्य,-प्रतिवादी

। 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 1820।

19 जुलाई 1988.

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम (1914 का प्रथम)–एस.एस. 31 और 32-पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956-आरएल। 37 (29, 30 और 31) - उत्पाद शुल्क का भुगतान - प्रचलित दरों पर शुल्क का भुगतान - बाद में उत्पाद शुल्क में वृद्धि - शुल्क भुगतान स्टॉक पर बढ़ी हुई शुल्क की मांग - ऐसी मांग की वैधता।

यह माना गया कि एक बार जब उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु पर शुल्क लगाया जाता है तो वह वस्तु नए या अतिरिक्त शुल्क के अधीन होने के चरित्र को खो देगी। इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा 31 मार्च, 1986 की समाप्ति तक बिना बिके रहे स्टॉक पर बढ़ी हुई ड्यूटी की मांग करना उचित नहीं था। की गई मांग स्पष्ट रूप से अवैध है और कानून के अधिकार से परे है।

(पैरा 4 और 8). भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

प्रार्थना है कि:-

(ए) संलग्नक पी. 2 और पी. 3 में निहित विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त सर्टिओरी या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी;

बी) कोई अन्य राहत जिसका याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है, वह कृपया याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए।

(सी) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने और उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी करने से छूट दी जाए।

और

(डी) रिट याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता से इस दौरान बढ़ी हुई ड्यूटी वसूलने से रोका जाए रिट याचिका का लंबित होना.

याचिकाकर्ता के वकील एस. सी. कपूर।

प्रतिवादियों की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता और अजय कुमार मित्तल, अधिवक्ता।

प्रलय

गोकल चंद मितल, जे.

(1) क्या उस समय देय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर खरीदी गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एकत्र किया जा सकता है, इन रिट याचिकाओं में विचार का मुद्दा है।

2) 18 रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ताओं के पास या तो भारतीय निर्मित विदेशी शराब (इसके बाद 'आईएमएफएल' कहा जाएगा) के थोक बिक्री डीलर के रूप में एल-1 लाइसेंस हैं या आईएमएफएल की खुदरा बिक्री के लिए एल-2 लाइसेंस हैं। पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 31 और 32 के तहत

(संक्षेप में 'अधिनियम'), जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ पर लागू है, रु. 3 मार्च, 1986 तक प्रति प्रूफ लीटर देय उत्पाद शुल्क के रूप में 22 रुपये तय किए गए थे। अधिसूचना अनुलग्नक पी. 1 दिनांक 27 मार्च, 1986 द्वारा, देय उत्पाद शुल्क रुपये से बढ़ाया गया था। 22 से रु. 27 प्रति प्रूफ लीटर, 1 अप्रैल 1986 से देय। अधिनियम की योजना के तहत, एक थोक व्यापारी जिले के उत्पाद शुल्क अधिकारियों से शुल्क भुगतान परमिट प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि आवश्यक शुल्क जमा करने पर परमिट मिलता है। जिले में प्रस्तुत किये गये हैं टिलर, जो एल-1 लाइसेंसधारी को आईएमएफएल की आवश्यक मात्रा जारी करते हैं। एल-1 लाइसेंसधारियों से, खुदरा डीलर, जिनके पास एल-2 लाइसेंस है, खुदरा बिक्री के लिए आवश्यक शराब की तलाश करते हैं। एल-2 डीलरों को दोबारा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि एल-एल डीलर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद शराब प्राप्त करता है और उसके बाद खुदरा डीलरों को बेच देता है।

(3) उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त-सह-कलेक्टर, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने 30 सितंबर, 1986 को ज्ञापन, अनुलग्नक पी 2 जारी किया, जिसमें लाइसेंसधारियों से आईएमएफएल के अपने शुरुआती स्टॉक

पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का आह्वान किया गया। 1 अप्रैल, 1986 से, रुपये की बढ़ी हुई दर पर. 27 प्रति प्रूफ लीटर,

(अर्थात् 5 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की वृद्धि), क्योंकि उस स्टॉक पर उन्होंने रुपये की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। 22 प्रति प्रूफ लीटर, खरीद उस तारीख से पहले की गई है। डीलरों ने उत्पाद शुल्क और कराधान आयोग, चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर करके आदेश को चुनौती दी, लेकिन असफल रहे, क्योंकि इसे खारिज कर दिया गया था, - दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 के आदेश, अनुलग्नक पी. 3 के तहत। उपरोक्त आदेश अलग से पारित किए गए थे। प्रत्येक लाइसेंसधारी के मामले को 1987 की विभिन्न रिट याचिकाओं संख्या 3984 से 3995, 4006 से 4008, 4480 और 4701 और 1820 में चुनौती दी गई है। चूंकि उनमें कानून का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए उनका निपटारा इस सामान्य तरीके से किया जा रहा है।

निर्णय.

(4) लाइसेंस 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए दिए जाते हैं। हमने दो मामलों का फैसला किया है, एक सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा इस कोर्ट की डिवीजन बेंच का। वे बॉम्बे राज्य बनाम मेसर्स एस.एस. मिरांडा लिमिटेड (1), और मेसर्स में रिपोर्ट किए गए हैं। भजन लाई सरन सिंह और कॉमरेड

पैनी बनाम पंजाब राज्य (2)। एस.एस. मिरांडा के मामले (सुआरा) में तथ्य यह थे कि लाइसेंस की अवधि के दौरान, जो अप्रैल से मार्च तक थी, 16 दिसंबर, 1948 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत विदेशी शराब पर शुल्क दोगुना कर दिया गया और लाइसेंसधारी को बुलाया गया। शराब पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए जो अभी भी अपने गोदामों में बिना बेची पड़ी थी, हालांकि इसे प्रारंभिक खरीद के समय देय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद लाइसेंसधारी द्वारा बहुत पहले खरीदा गया था। बॉम्बे एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया कि लाइसेंसधारी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। भजन लाई सरन सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया गया था।

निम्नलिखित अंश पुनः प्रस्तुत किये जाने योग्य है:

ए

..बॉम्बे राज्य बनाम मैसर्स में। एस.एस. मिरांडा लिमिटेड मझगांव का मानना था कि एक बार कुछ वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, उसी सामान के संबंध में उत्पाद शुल्क के रूप में अतिरिक्त राशि केवल इस आधार पर वसूली योग्य नहीं होगी कि शुल्क की दर बाद में तय की गई है।

उन्नत. उनके आधिपत्य ने देखा कि वे एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को नहीं देख सकते थे जिस पर शुल्क लगाया गया था, आगे शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा और न ही दर में वृद्धि के मामले में अंतर के लिए उत्तरदायी होगा। तत्काल मामले में समान सिद्धांतों को लागू करने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार थोक व्यापारी द्वारा उठाए गए स्टॉक के संबंध में स्टिल-हेड ड्यूटी के रूप में जाना जाने वाला उत्पाद शुल्क लगाया गया था; बंधुआ गोदाम या शराब के निर्माता से, जैसा भी मामला हो, शराब के निर्माण, या उत्पादन के साथ उक्त शुल्क का संबंध समाप्त हो गया था, और उस स्थिति में, थोक विक्रेता को खुद को वसूल करना होगा उसके द्वारा भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की सीमा तक, उसे उसके द्वारा वसूल की जाने वाली कीमत में शामिल करके, लेकिन उक्त वस्तु उत्पाद शुल्क का चरित्र खो देगी और राज्य द्वारा उस पर लगाया जाना बंद हो जाएगा।

"उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक बार जब उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु शुल्क के अधीन हो जाती है, तो वस्तु नए या अतिरिक्त शुल्क के अधीन टोइंग के चरित्र को खो देगी और उपरोक्त कारण

आईएनजी हाथ में आए मामले पर लागू होता है।

एस.एस. मिरांडा के मामले (सुप्रा) में, उत्पाद शुल्क को उत्पाद वर्ष की मुद्रा के दौरान बढ़ाया गया था, जबकि वर्तमान मामले में उत्पाद शुल्क को वर्ष की समाप्ति के बाद बढ़ाया गया था।

इस मामले को पक्षों को दिखाने के लिए विद्वान वकील के समक्ष रखा गया

अगर इससे कोई फर्क पड़ेगा. स्थगित सुनवाई पर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह दिखाने में सक्षम नहीं थे कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। उन्होंने पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 (संक्षेप में 1958 के नियम) के नियम 37 के उप-नियम 29, 30 और 31 का उल्लेख किया। नियमों के उप-नियम 29 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो लाइसेंसधारी भी है, उसके पास लाइसेंस की समाप्ति या निर्धारण पर कोई नशीला पदार्थ है, जिसे वह निपटाने में असमर्थ है, तो उसे तुरंत इसे कलेक्टर को सौंप देना होगा। और कलेक्टर

इसे आने वाले लाइसेंसधारी को सौंप सकता है। उप-नियम 30 में यह प्रावधान है कि जिस लाइसेंसधारी को ऐसा नशीला पदार्थ सौंपा गया है, वह उस कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जो कलेक्टर द्वारा उस पर खर्च की गई वास्तविक राशि या प्रचलित राशि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है।

।बाजार कीमत। उप-नियम 31 में यह प्रावधान है कि कलेक्टर उस निवर्तमान लाइसेंसधारी को भुगतान की गई कीमत का भुगतान करेगा, जिसके द्वारा मादक पदार्थ को आत्मसमर्पण किया गया था, लाइसेंसधारी से वसूली योग्य शुल्क, शुल्क या जुर्माना, यदि कोई हो, की राशि में से कटौती करने के बाद। ये उप-नियम उत्तरदाताओं की सहायता नहीं करते हैं। बल्कि वे लाइसेंसधारी के मामले का समर्थन करते हैं। तर्कों के लिए

यह मानते हुए कि लाइसेंस में; ये मामले 31 मार्च, 1986 को समाप्त हो गए, 1 अप्रैल, 1986 को उनके पास पड़े बिना बिके स्टॉक को कलेक्टर को सौंप दिया गया, जिसे नए लाइसेंसधारी को इसे सौंपना था और वास्तविक मूल्य या प्रचलित मूल्य एकत्र करने के बाद उनसे/उनसे बाजार मूल्य, निवर्तमान लाइसेंसधारी को समान भुगतान करना था। इसलिए, उत्पाद शुल्क में वृद्धि, जो 1 अप्रैल से लागू हुई,1986, कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

(6) मेरे सामने आए मामलों में सभी लाइसेंसधारक इस प्रकार शामिल हैं। 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी नए लाइसेंसधारी। इसलिए, नियमों के नियम 37 के उप-नियम 29 से 31 लागू नहीं होते हैं, और लाइसेंसधारी नए लाइसेंस के तहत स्टॉक रखना जारी रखेंगे और, नियमों के अनुसार माल का निपटान करेंगे। यह अतिरिक्त कारण है कि लाइसेंसधारियों को उत्पाद शुल्क में अंतर की भरपाई करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

(7) बहस के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि 1986-87 के दौरान उत्पाद शुल्क रुपये की दर से था। 27 प्रति प्रूफ लीटर, जिसे वर्ष 1987-88 के लिए बढ़ाकर रु. 29 प्रति प्रूफ लीटर और चालू वर्ष यानी 1988-89 के लिए इसे घटाकर रु. 26 प्रति प्रूफ लीटर, और अधिकांश याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी बने रहे। शुल्क कम होने की तिथि पर याचिकाकर्ताओं के पास जो स्टॉक पड़ा था, उसके लिए उन्हें कोई रिफंड की अनुमति नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि राज्य को बढ़ी हुई ड्यूटी वसूलने का अधिकार है, तो उसी तरह उसे उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण राशि वापस करने के लिए बाध्य होना चाहिए, यदि यह कानून द्वारा प्रदान किया गया था . इन आधारों पर यह तर्क दिया गया है कि चाहे वृद्धि हुई हो या कमी, किसी भी स्थिति में न तो अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है और न ही वापसी योग्य है।

(8) उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा उस स्टॉक पर बढ़े हुए शुल्क की मांग करना उचित नहीं था, जो 31 मार्च, 1986 की समाप्ति तक बिना बिके रह गया था, न ही उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए न ही ऊपर उल्लिखित उप नियमों के तहत निर्णयों का हवाला दिया गया है, और की गई मांग स्पष्ट रूप से अवैध है और कानून के अधिकार से परे है।

9) ऊपर दर्ज कारणों से, सभी सिविल रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त-सह-कलेक्टर, यू.टी. का आदेश स्वीकार किया जाता है। चंडीगढ़, जिसे चंडीगढ़ के उत्पाद शुल्क एवं

कराधान आयुक्त द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था, को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा